

सूरत भूमि

हिन्दी दैनिक

संपादक : संजय आर. मिश्रा

वर्ष-10 अंक: 242 ता. 22 मार्च 2022, मंगलवार, कार्यालय: 114, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेंट, डिंडोली, डिंडोली, उधना सूरत (गुजरात) मो. 9327667842, 9825646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये

ho@suratbhumi.com

/Suratbhumi.com

/Suratbhumi

/Suratbhumi

/Suratbhumi

/Suratbhumi

संक्षिप्त समाचार



मुख्यमंत्री पद पर पुष्कर सिंह धामी की फिर हुई वापसी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुई विधानमण्डल दल की बैठक में सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री घोषित किया गया। बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा पार्टी को जीत के लिए मन्दिरो व धार्मिक स्थलों में गृहार लगाने जगह-जगह पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के गृहार को मां नयना देवी, शिव जी व गोल्लू देवता समेत सभी धार्मिक स्थलों के परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया। जहां भगवान ने मुख्यमंत्री धामी की गृहार स्वीकार कर ली, पर वह अपनी सीट नहीं बचा पाये। पार्टी की जीत के लिए मां नयना देवी मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने शिवलिंग में जल, दूध से स्नान कराया। वहीं उन्होंने घोड़ाखाल गोल्लू मन्दिर में भी भाजपा पार्टी व अपनी जीत के लिए गृहार लगाई थी। भाजपा पार्टी को तो बहुत मदद के साथ ले आये, पर अपनी सीट नहीं बचा पाये। वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पुनः मुख्यमंत्री की ताजपोशी कर दी है। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ नैनीताल वासियों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जबकि मुख्यमंत्री के पास अभी बड़ी चुनौती है।

हिमाचल कांग्रेस में खलबली, वर्तमान विधायक सहित चार पूर्व विधायक आप में जाने की जुगत में

शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति बन गई है सोशल मिडिया द्वारा एक पोस्टर में एक मौजूदा विधायक सहित चार पूर्व विधायकों के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है। जिससे प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई है। प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं। जिससे कई नेता अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिये आम आदमी पार्टी का दामन धामने की तैयारी में हैं। इस मामले को लेकर सोशल मिडिया में अच्छी खासी बहस छिड़ी है। लोग पूर्व विधायकों के आप में आने का विरोध भी कर रहे हैं। जाने माने चिंतक देवाशीष भट्टाचार्य ने अपनी पोस्ट में कहा है कि हिमाचल उस आप को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भाजपा या कांग्रेस के क्रॉसओवर से प्रभावित होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमाचल में आप यह गलती नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी में हिमाचल प्रदेश के आम व्यक्ति शामिल होने चाहिए न कि भाजपा और कांग्रेस के वीआईपी। प्रवासी पक्षियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। दरअसल, सोशल मिडिया पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा, पूर्व सीपीएस जगजीवन पाल, जयसिंहपुर से पूर्व विधायक यादवदेव गोमा, कांगड़ा के मौजूदा विधायक पवन काजल व ज्वालामुखी के पूर्व विधायक संजय रतन के आम आदमी पार्टी में शामिल होने का पोस्टर वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को बदले हालातों में लगने लगा है कि आने वाले चुनावों में उनका टिकट कट सकता है। ऐसे नेता अभी से ही अपना नया ठेरा ठिकाना तलाशने लगे हैं। ऐसे नेता अभी से ही अपना नया ठेरा ठिकाना तलाशने लगे हैं।

सुरक्षा बलों को कार्रवाई की पूरी छूट, आतंकी फंडिंग के सभी नेटवर्क तुरंत ध्वस्त करो : अमित शाह



नई दिल्ली।

दो दिनों के दौर पर जम्मू कश्मीर आए गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के लिए फंड जुटाने

जेल में बंद अलगाववादी नेता मसरत आलम, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, बिजू कार्टे जैसे लोगों के संपर्क में हैं। जो इनके इशारे पर देश-विदेश में बैंकर गतिविधियों पर अंकुश लगाने को कहा है। शाह ने कहा सुरक्षा बल जल्द से जल्द आतंकी फंडिंग के सभी नेटवर्क को ध्वस्त करें। पार्टी में बड़ी संख्या में कारोबारियों और स्थानीय लोगों का नेटवर्क है, तो विभिन्न तरीके से आतंकीयों की सहायता करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी कई लोग

थिंक टैंक राज्यसभा में आप के 33 वर्षीय राघव चड्ढा सहित अन्य 10 नौजवान सांसदों का होगा जालवा

नई दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल कर आम आदमी पार्टी (आप) ने अब राज्यसभा सीटों के लिए अपने पांच उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है। इसमें पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ दिल्ली के 33 साल के विधायक राघव चड्ढा का नाम भी शामिल है। राज्यसभा को कभी रिटायर हो चुके लोगों का हाउस माना जाता था, लेकिन अब वहां भी युवाओं की संख्या बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा 33 साल में सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बनने की राह पर हैं। राज्यसभा की इन सीटों पर 31 मार्च को मतदान होगा। चूंकि आप के पास पंजाब विधानसभा में 117 में से 92 सीटों के साथ बहुमत है, इसलिए उसके सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। इससे राज्यसभा में आप सांसदों की संख्या अब तीन से बढ़कर आठ हो जाएगी। राघव चड्ढा इस समय दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक हैं। उनको 2020 में पंजाब का सह प्रभारी नियुक्त किया गया था और वह पंजाब में आप की रणनीति को लागू करने के लिए लगातार पंजाब में बने रहे। पार्टी की स्थिति को साफ तौर से लोगों के सामने रखने के साथ-साथ विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इससे साफ है कि न केवल मीडिया में बल्कि जमीन पर एक प्रचारक के रूप में भी युवा विधायक की बड़ी सफलता को देखते हुए पार्टी की अभूतपूर्व जीत के बाद अब पंजाब में उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अलावा राघव चड्ढा को आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का भरोसा हासिल है। चड्ढा दिल्ली और पंजाब के बीच की कड़ी हैं और उम्मीद है कि वह पंजाब सरकार के काम पर नजर रखेंगे। इससे पहले मैरी कॉम 35 साल की उम्र में सांसद बनी थी और 34 साल की उम्र में रितावत बनजी ने राज्यसभा की सदस्यता हासिल की थी। अब राघव चड्ढा केवल 33 साल की उम्र में राज्यसभा के सदस्य की शपथ लेने वाले सबसे कम उम्र के सांसद होंगे। केजरीवाल वफादार और भरोसेमंद सहयोगी चड्ढा पार्टी के सबसे कम उम्र के प्रवक्ता थे। चड्ढा ने दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जल सुधारों पर काम किया। चड्ढा को दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी तरह क्रिकेटर से राजनेता बन रहे हरभजन सिंह को उम्र भी केवल 41 साल है। पार्टी को उम्मीद है कि वह पंजाब में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, खेल विश्वविद्यालय बनाने और युवाओं के साथ पार्टी के संबंध को मजबूत करने में मदद करने के लिए काम करेंगे। हरभजन सिंह के पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान के साथ अच्छे संबंध हैं। इसके साथ ही वे भी राज्यसभा के कम उम्र के सांसदों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा सीपीएम ने भी इस बार केरल से एक युवा चेहरे को राज्यसभा सीट के उम्मीदवार के लिए चुना है। यह फैसला पार्टी के नेतृत्व और संसदीय पदों में पीढ़ीगत बदलाव लाने के प्रयास के अनुरूप लिया गया। माकपा ने 40 साल के एए रहीम को 31 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए माकपा ने 40 साल के एए रहीम को 31 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने का फैसला किया है। वे केरल से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के नेताओं में से एक हो सकते हैं। कई दलों ने अपने युवा कार्यकर्ताओं को राज्यसभा भेजा है।

शपथ ग्रहण समारोह को मत्स्य बनाने के लिए तैयारियों जोर-शोर में

यूपी में 25 मार्च को शपथ लेंगे योगी, पीएम मोदी भी शपथग्रहण में लेंगे हिस्सा

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए प्रशासन जोर-शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च की शाम चार बजे राजधानी में शहीद पथ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी

इकाना स्टेडियम में किया जाएगा। भाजपा ने शपथ ग्रहण में भाग लेने वाले अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। भाजपा ने कहा है कि शपथ ग्रहण के दिन कार्यकर्ता सुबह 8 बजे से 10 बजे तक भगवान की पूजा करें। भाजपा के निर्देश में यह भी कहा गया है कि सभी अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र से शपथ ग्रहण

समारोह में शामिल हों। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो लोग गाड़ी से आ रहे हैं, वे अपनी गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगाएं। अपर मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत महलाने इकाना स्टेडियम का दौरा किया और स्टेडियम प्रबंधन के साथ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर विस्तार में चर्चा की। सहलगने ने बताया कि

शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां मुख्य सचिव डीएस मिश्रा के नेतृत्व में की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में करीब 75 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। भाजपा

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के शपथ ग्रहण में शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कई मंत्रियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों

के भी शामिल होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वादा सहित विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा।

वर्चुअल समिट में पीएम मोदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ संबंधों की बात की

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों की प्रगाढ़ता पर कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए एक तंत्र स्थापित करना प्रसन्नता का विषय है। भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट के एक ओपन सेशन में बोलते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि यह तंत्र हमारे संबंधों की नियमित समीक्षा के लिए एक संरचनात्मक प्रणाली तैयार करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन को प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को वापस करने की पहल के लिए भी धन्यवाद दिया, जिनका उन्होंने वर्चुअल समिट से पहले निरीक्षण किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 29 पुरावशेषों, मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों में बनाई गई मूर्तियां और पेंटिंग्स, भारत को लौटाई हैं। ये पुरावशेष छह श्रेणियों, 'शिव और उनके शिष्यों', 'शक्ति की पूजा', 'भगवान विष्णु और उनके रूप', 'जैन परंपरा', चित्र और सजावटी वस्तुओं से नाता रखते हैं। स्कॉट मॉरिसन ने यूकेन में रूस की आक्रमकता के मद्देनजर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते बदलाव के खतरे के बारे में बात की। इस क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख का एक स्पष्ट संदर्भ में, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि क्राइ नेताओं द्वारा यूकेन पर रूस के गैरकानूनी आक्रमण पर चर्चा करने का आह्वान भी इंडो-पैसिफिक रीजन के लिए उस भयानक घटना के निहितार्थ और परिणामों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है, जिन मुद्दों का हम यहां सामना करते हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने इस शिखर वार्ता के दौरान यूकेन पर रूसी आक्रमण का उल्लेख नहीं किया और अपनी टिप्पणियों को भारत-ऑस्ट्रेलिया के साझा मूल्यों और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति पर केंद्रित रखा। उन्होंने कहा, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और नवाचार, विज्ञान और उद्योग, कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे खनिज, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है।

तेलंगाना में शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद गरमाया

नई दिल्ली। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर हुए विवाद के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से सोमवार को बंद का आह्वान किया गया जिसके बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। दरअसल रविवार को अंबेडकर क्रॉसरोड स्थित शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने को लेकर दो पक्षों में तनाव हो गया था। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंशु गैस के गोले छोड़े पड़े। शिवाजी महाराज की मूर्ति ना लगाने देने के विरोध में सोमवार को बीजेपी ने बंद बुलाया। दूसरी तरफ निजामाबाद पुलिस कमिश्नर केआर नागावजु ने धारा 144 लगाते का ऐलान करते हुए कहा कि कानून तोड़ने की कोशिश करने वालों से निपटा जाएगा। इस दौरान प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी साथ ही ये भी कहा गया है कि दुकानदारों को दुकान खोलने से रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें भी सामान्य रूप से चल रही हैं। शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प अब राजनीतिक रंग भी लेती जा रही है। निजामाबाद से बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि वो शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाने की कोशिश ना करें।

अशोक मित्तल: पहले बने हलवाई, फिर यूनिवर्सिटी के चांसलर, अब जाएंगे राज्यसभा

चंडीगढ़।

पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी राज्यसभा में भी अपनी ताकत परचम फहराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी ने सोमवार को राज्यसभा के लिए जिन पांच नामों का ऐलान किया उनमें पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर अशोक मित्तल का नाम भी शामिल है। वह देश के सफल उद्योगपतियों में से हैं। बता दें उनकी यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक है। तकरीबन 6 सौ एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी में 50 से ज्यादा देशों के छात्र पढ़ते हैं। बताया जाता है कि अशोक मित्तल की फैमिली भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद

जालंधर आकर बस गई थी। यहां उनके पिता स्वर्गीय बलदेव राज मित्तल ने मिठाई की दुकान से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। जिसका नाम था लवली डीलरशिप देने से इंकार कर दिया था। मगर बाद में उन्हें बजाज की डीलरशिप मिल गई। वर्ष 1991 में अशोक मित्तल ने लवली नाम से ही ऑटो की डीलरशिप का काम शुरू किया। इस क्षेत्र में उनकी किस्मत ने साथ दिया। महज 5 साल में उन्हें मारुति सुजुकी की भी डीलरशिप मिल गई। अपनी मेहनत के दम पर कुछ समय में ही लवली ऑटो का नाम पंजाब की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप में शामिल हो गया। अशोक मित्तल ने बजाज की डीलरशिप लेने का फैसला किया,

मगर ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में कपनी ने एक मिठाईवाले को डीलरशिप देने से इंकार कर दिया था। मगर बाद में उन्हें बजाज की डीलरशिप मिल गई। वर्ष 1991 में अशोक मित्तल ने लवली नाम से ही ऑटो की डीलरशिप का काम शुरू किया। इस क्षेत्र में उनकी किस्मत ने साथ दिया। महज 5 साल में उन्हें मारुति सुजुकी की भी डीलरशिप मिल गई। अपनी मेहनत के दम पर कुछ समय में ही लवली ऑटो का नाम पंजाब की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप में शामिल हो गया। अशोक मित्तल ने बजाज की डीलरशिप लेने का फैसला किया,



में सफलता प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। सफलता प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल कॉलेज की नींव रखी। यह यूनिवर्सिटी में बदल गई। लवली ग्रुप शिक्षा, मिठाई और ऑटोमोबाइल डीलरशिप श्रेणियों में लगभग 800 करोड़ रुपये का समूह है।

मणिपुर 5 कैबिनेट मंत्रियों संग बीरेन सिंह ने ली सीएम पद की शपथ

नई दिल्ली। मणिपुर में एक बार फिर एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बन गए हैं। एन बीरेन सिंह ने सोमवार को इंकाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीरेन सिंह के साथ ही पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें नेमाचा किपजेन, वाई, खेमचंद सिंह, बिस्वजीत सिंह, अवंगबो न्यूमाई और गोविंदस कोथोंजम शामिल हैं। बीरेन सिंह ने जेपी नड्डा और अन्य भाजपा नेताओं की उपस्थिति में दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। एक दिन पहले ही एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया था। शपथ लेने के बाद बीरेन सिंह ने कहा कि मेरी सरकार का पहला कदम इसे छत्रचार मुक्त राज्य बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मैं राज्य से छत्रचार को मिटाने के लिए दिन-रात काम करूंगा। अगला कदम यह होगा कि राज्य से किसी भी तरह के मादक पदार्थ संबंधी मामले को खत्म किया जाए। तीसरा मैं यह देखने की कोशिश करूंगा कि राज्य में सक्रिय सभी द्विदलियों को बातचीत की मेज पर लाया जाए और संवाद हो। ये तीनों मेरे प्राथमिक कर्तव्य होंगे। इससे पहले रविवार को मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन ने भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। जिसमें कहा गया कि एन बीरेन सिंह को सर्वसम्मति से 32 विधायकों के साथ भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है

मध्य रेल द्वारा टिकट चेकिंग से 200 करोड़ की राजस्व अर्जित

मुंबई।

मध्य रेल ने वास्तविक रेल उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और टिकट रहित यात्रा पर अंकुश लगाने के अपने प्रयास में, उपनगरीय, मेल, एक्सप्रेस, यात्री और स्पेशल ट्रेनों में टिकट रहित और अनियमित यात्रा के खिलाफ नियमित रूप से सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया है। इसके अलावा, रिवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए, मध्य रेल की सतकटा टीम टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ टिकट रहित यात्रा के खिलाफ भी इस तरह के अभियान चलाती है।

अप्रैल 2021 से 16 मार्च 2022 (1.4.2021 से 16.3.2022) की अवधि के दौरान कुल 33.30 लाख मामले पकड़े गए और 200.85 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो सभी क्षेत्रीय रेलों में मामले और राजस्व के संबंध में सबसे अधिक है। यह कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद मध्य रेल की अब तक की सबसे अधिक आय है। मुंबई मंडल ने बिना टिकट और अनियमित यात्रा के 12.93 लाख मामले पकड़े हैं, जिनसे 66.84 करोड़ रुपये वसूल किए हैं, जो मध्य रेल के सभी मंडलों में सबसे अधिक है। धुसावल

मंडल ने अनियमित यात्रा के 8.15 लाख मामले पकड़े हैं, जिनसे 58.75 करोड़ रुपये वसूल किए हैं, नागपुर मंडल ने अनियमित यात्रा के 5.03 लाख मामलों से 33.32 करोड़ वसूल, सोलापुर मंडल ने अनियमित यात्रा के 3.36 लाख मामले पकड़े गए और उनसे 19.42 करोड़ रुपये वसूल और पुणे मंडल ने अनियमित यात्रा के 2.05 लाख मामले पकड़े और उनसे 10.05 करोड़ रुपये वसूल की गई हैं। मुख्यालय के टिकट चेकिंग दल ने बिना टिकट और अनियमित यात्रा के 1.80 लाख मामले पकड़े और उनसे

12.47 करोड़ रुपये की वसूल किए हैं। उपरोक्त के अलावा, इस अवधि के दौरान सभी 56,443 व्यक्तियों को कोविड अनुरूप व्यवहार का उल्लंघन करने और मास्क न पहनने हुए पाया गया और उनसे 88.78 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। मध्य रेल यात्रियों से अपील करता है कि असुविधा से बचने के लिए उचित और वैध रेलवे टिकट के साथ यात्रा करें और गिरफ्तार के साथ यात्रा करें और अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए कोविड -19 अनुरूप व्यवहार का पालन करें।



लोस- अधीर रंजन चौधरी बोले- 'दिशा' समिति की बैठकों को अनिवार्य बनाया जाए

नई दिल्ली। लोकसभा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिलों में सांसदों के नेतृत्व वाली 'दिशा' समिति की बैठकों को अनिवार्य बनाने की मांग करते हुए सोमवार को कहा कि जिन राज्यों में ये बैठकें नहीं होती हैं वहां विकास कार्य से संबंधित निधि गेकी जाए। चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछते हुए यह दावा भी किया कि पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों से 'दिशा' समिति की बैठकें नहीं हो रही हैं। उन्होंने दावा किया, 'पिछले 12-13 साल से मेरे यहां दिशा समिति की बैठक नहीं बुलाई गई है, जबकि मैं दिशा समिति का प्रमुख हूँ। किसी भी मंत्रालय से जुड़े विषय पर दिशा समिति की बैठक नहीं बुलाई जाती है।' पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से लोकसभा सदस्य चौधरी ने कहा, 'यह अनिवार्य कर दीजिए कि अगर दिशा समिति बैठक नहीं बुलाई जाती है तो फिर फंड रिलीज होना बंद कर दीजिए। हर राज्य को मजबूर किया जाए कि बैठक बुलाई जाए।'

एलआईसी आईपीओ लाने के लिए केंद्र सरकार ने सेबी के पास अद्यतन दस्तावेज जमा करवाए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बहुप्रतीक्षित आर्थिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) लाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के पास अद्यतन दस्तावेज जमा करवा दिए हैं, इन दस्तावेजों में दिसंबर तिमाही से जुड़ी जानकारी शामिल है। सेबी ने एलआईसी द्वारा 13 फरवरी, 2022 को दायित्व दस्तावेजों के मसौदे (डीआरएचपी) को मंजूरी दे दी थी। इनमें सितंबर तक के वित्तीय नतीजों की जानकारी थी। एक अधिकारी ने बताया, 'दिसंबर के नतीजों के साथ एलआईसी के अद्यतन दस्तावेज (डीआरएचपी) दायित्व कर दिए गए हैं।' नवीनतम जानकारी के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एलआईसी को 235 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच शुद्ध मुनाफा बढ़कर 1,671.57 करोड़ रुपये हो गया। सरकार को एलआईसी के लगभग 31.6 करोड़ शेयरों या पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की विक्री के जरिए आईपीओ के माध्यम से करीब 60,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है।

पुनीत चटवाल भारतीय होटल संघ के फिएर अध्यक्ष बने

नई दिल्ली। भारतीय होटल संघ (एचएआई) ने संस्था के शीर्ष पद पर पुनीत चटवाल को फिर से अध्यक्ष चुन लिया है। चटवाल इंडियन होटल्स कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। एचएआई ने एक बयान में कहा कि कार्यकारी समिति ने प्रबंधन समिति को दो वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए चुनने का फैसला आम सहमति से लिया। होटल संघ की सालाना आम सभा पिछले हफ्ते हुई थी। इसके बाद, चार प्राथमिकताओं के चयन के लिए कार्यकारी समिति की बैठक हुई। इनमें चटवाल के अलावा हैं उपाध्यक्ष केबी काचरू, मानद सचिव जेके मोहंती और मानद कोषाध्यक्ष पापू कंसवानी।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अडाणी ग्रीन एनर्जी ने 28.8 करोड़ डॉलर की राशि एकत्र की

नई दिल्ली। पाँच सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के लिए 28.8 करोड़ डॉलर (करीब 2,188 करोड़ रुपये) की राशि जुटाई है। कंपनी ने एक बयान में कहा, 'अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने कुछ अंतरराष्ट्रीय कर्जदाताओं के समूह के साथ समझौता करके अपनी निर्माणधीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 28.8 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है और इस तरह अपने कस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क को 1.64 अरब डॉलर तक का कर लिया है।' इस राशि का इस्तेमाल राजस्थान में एजीईएल की 450 मेगावाट क्षमता वाली सोर और पवन नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। एजीईएल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी विनीत एस जैन ने कहा, 'एजीईएल की पूंजी प्रबंधन योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है निर्माण इकाई जो ऊर्जा उत्पादन को कार्बन मुक्त करने के हमारे उद्देश्य में मदद देती है।'

राकेश टिकैत का विमान आसमान में खाने लगा हिचकोले, लोग बोले- किसान तो गरीब होता है पलाइंट के पैसे कहां से आए

नई दिल्ली। हवाई यात्रा का सुख तो होता है पर जब आसमान में विमान हिचकोले लेने लगे तो जान सांसत में आ जाती है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हेदराबाद से इंडिगो एयरलाइन्स के विमान से त्रिचीपल्ली जा रहे थे। इस दौरान आसमान में उनका विमान कलाबाजियां खाने लगा। करीब आधे घंटे तक विमान आसमान में कलाबाजियां खाता रहा। राकेश टिकैत ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया, हेदराबाद से त्रिचीपल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइन नं. 6ई 7213 शनिवार शाम 7:10 बजे खराब मौसम की वजह से आसमान में कलाबाजियां खाने लगी। आधा घंटे तक मेरी और मुसाफिरो की जान आफत में रही। इतनी खतरनाक उड़ान की इजाजत उचित नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए। टिकैत के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने खूब मजे लिए। एक यूजर ने लिखा कि किसान तो गरीब होता है उसके पास पलाइंट के पैसे कहां से आए? वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि जानबूझकर आपकी बेहद कीमती जान को मौसम ने खतरे में डाला, पूज्य वरुण देव के खिलाफ इसकी जांच होनी चाहिए। किसी ने लिखा कि धरना दो भाई इसके खिलाफ। यह तो एकदम नया मुद्दा है। इस बार सड़क जाम करने की बजाए आकाश मार्ग जाम करो। एक यूजर ने लिखा कि इसमें जरूर भाजपा की कोई चाल है, बीजेपी ने जानबूझ कर मौसम खराब करवाया है। एक यूजर ने लिखा कि इसमें जरूर भाजपा की कोई चाल है।

पाक अधिकृत कश्मीर को आजाद कराने के लिए केंद्र सरकार कृतसंकल्प : जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कटुआ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मोदी सरकार ने अपने पिछले दो कार्यकाल में कई ऐसे बड़े कदम उठाए हैं, जो सालों से विवादों में थे। मोदी सरकार ने अपनी सुझबूझ से इन राजनीतिक मुद्दों को हमेशा के लिए सुलझा दिया है। इन मुद्दों पर सालों तक राजनीति होती रही और राजनीतिक पार्टियों ने इसको ढाल बनाकर खूब

चुनाव प्रचार किया। चाहे वह 30 सालों से उलझा राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कश्मीर में लगी धारा 370, सरकार ने कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए और विवाद को खत्म किया। आज जम्मू कश्मीर के हालात काफी अच्छे हो गए हैं, वहीं राम मंदिर का मुद्दा सलझने से लोग इतने खुश हैं कि योगी सरकार को प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से राज्य में लेकर आ गए सुलझा दिया है। इन मुद्दों पर सालों तक राजनीति होती रही और राजनीतिक पार्टियों ने इसको ढाल बनाकर खूब

सरकार पर लोग विश्वास करते हैं। अब पीओके को लेकर मोदी सरकार के मंत्री ने जो बात कही है, वह भारतीयों को गर्व से भर देगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को भारतीय क्षेत्र में फिर एकीकृत करने के अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के कटुआ में महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा 1994 में

प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारतीय संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की एकमात्र वजह पीओके है। सिंह ने जोर देकर कहा, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि जम्मू-कश्मीर का वह हिस्सा, जो अभी भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, भारतीय क्षेत्र में फिर से एकीकृत हो गया है। उन्होंने कहा जब भाजपा कोई पहल करती है तो कुछ लोग हमें गंभीरता से नहीं लेते हैं या इसके बारे



में गहराई से नहीं सोचते हैं। जब हम धारा 370 को खत्म करने की बात करते थे तो कई लोग हमारा भजाक उड़ाते थे। लेकिन, आपने इसे हकीकत में बदलते देखा है। भाजपा पार्टी का उद्देश्य किया जब पूर्व प्रधान मंत्री अटल घोषणा की कि कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा हर अधूरे काम को पूरा करेगी।

बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर मिले चीनी ड्रोन की जांच कर रही बीएसएफ

नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने कहा कि वह इस बात की जांच कर रहा है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक खेत में मिले चीनी ड्रोन का इस्तेमाल ट्रॉस-के लिए किया जा रहा था या नहीं। बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर कमांड के अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ सीमा चौकी कल्याणी से सटे गांव पुरबापारा के किसान को भारत-बांग्लादेश सीमा के पास एक खेत में चीन निर्मित एक टूटा हुआ ड्रोन मिला, जिसके बाद बीएसएफ सुरक्षा गढ़ा गया है। अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन को किसान ने 19 मार्च को शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 300 मीटर दूर एक खेत में पाया था। उन्होंने कहा कि किसान ने टूटे हुए ड्रोन को उठाकर स्थानीय पुलिस थाने के अधिकारियों को सौंप दिया। ड्रोन के बरामद होने की सूचना के बाद, कल्याणी चौकी से बीएसएफ की टीम सबूत खोजने के लिए मौके का दौरा किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के बीएसएफ अधिकारियों ने कहा कि कल्याणी चौकी के अधिकारियों ने ड्रोन के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आसपास के गांवों में भी पूछताछ की। ड्रोन के बरामद होने की सूचना के बाद, कल्याणी चौकी से बीएसएफ की टीम सबूत खोजने के लिए मौके का दौरा किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के बीएसएफ अधिकारियों ने कहा कि कल्याणी चौकी के अधिकारियों ने ड्रोन के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आसपास के गांवों में भी पूछताछ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत की पश्चिमी सीमा पर तैनात बीएसएफ और अन्य जैसी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, हथियार, गोला-बारूद और ड्रॉस ले जाने या निगरानी करने वाले ड्रोन के उभरते खतरे से जूझ रही हैं। यह शायद पहली बार था जब एक ड्रोन बांग्लादेश के साथ पूर्वी सीमा पर पाया गया था। बीएसएफ भारत-बांग्लादेश सीमा के कुल 4,096 किलोमीटर की सुरक्षा करती है, जिसमें पश्चिम बंगाल में इसका दायरा 2,217 किलोमीटर है।

धर्म व जाति के आधार पर लोगों को लड़ाते हैं सियासी दल, कांग्रेस भी इसकी अपवाद नहीं : आजाद

गुलाम नबी ने दिए राजनीति से संन्यास लेने के संकेत

श्रीनगर।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए राजनीतिक दलों की क्षमता को लेकर गंभीर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपने संबोधन में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के संकेत भी दिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा अब अक्सर भ्रम मन राजनीति से संन्यास लेकर समाज सेवा में सक्रिय होने का करता है। जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान नागरिक समाज के सदस्यों को संबोधित करते हुए, आजाद ने कहा कि हमको समाज में एक बदलाव लाना है। कभी कभी मैं सोचता हूँ और यह कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अचानक आप लोगों को पता चले कि मैं

सक्रिय राजनीति से रिटायर हो गया और समाज सेवा के कार्य में जुट गया हूँ। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता एमके भारद्वाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने 35 मिनट के संबोधन की शुरुआत में ही आजाद ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस मंच पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेगा। उन्होंने कहा भारत में राजनीति इतनी बदसूरत हो गई है कि कभी-कभी सदेह होता है कि हम इंसान हैं भी या नहीं। उन्होंने कहा हम सब अगर एक शहर को, एक प्रांत को ठीक करेंगे, तो पूरा हिंदुस्तान ठीक होगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, एक इंसान की क्षमता में एक बदलाव लाना है। कभी कभी मैं सोचता हूँ और यह कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अचानक आप लोगों को पता चले कि मैं



साथ आएंगे। के बीच 24म7 विभाजन पैदा करते हैं। मैं कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी को माफ नहीं कर रहा। नागरिक समाज को एक साथ रहना चाहिए। जाति, धर्म को देखे बिना सभी को न्याय दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और धर्मनिरपेक्ष थे। जम्मू-कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और उखावट जिम्मेदार हैं। इसने जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, मुसलमानों, डोगराओं सहित सभी को प्रभावित किया है।

नागरिक समाज को एक साथ रहना चाहिए। जाति, धर्म को देखे बिना सभी को न्याय दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और धर्मनिरपेक्ष थे। जम्मू-कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और उखावट जिम्मेदार हैं। इसने जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, मुसलमानों, डोगराओं सहित सभी को प्रभावित किया है।

राज्यसभा में उठा मार्च माह से गर्मी का प्रकोप शुरू होने का मुद्दा

नई दिल्ली।

राज्यसभा में सोमवार को सदस्यों ने मार्च महिने से ही गर्मी का प्रकोप शुरू होने, कोविड-19 रोधी टीकों की एहतियाती खुराक को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने और ऑनलाइन खेलों के बहते प्रचलन पर चिंता जताई और सरकार से इन विषयों को लेकर आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विकास महात्मे ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा कुछ राज्यों में लू को लेकर जारी की गई चेतावनी का उल्लेख करते

हुए कहा मार्च के महिने में ही लोग प्रचंड गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे गरीब और किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ चेतावनी जारी करना ही काफी नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह राज्यों को एक दिशा-निर्देश जारी करे कि उन्हें बचाव के क्या-क्या उपाय करने चाहिए। सरकार को सभी राज्यों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी करनी चाहिए। सभापति एम वैकेया नायडू ने भी मौसम में अचानक से आए इस बदलाव पर चिंता जताई और कहा कि यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा मार्च

में इतनी गर्मी है तो आगे क्या होगा? उन्होंने राज्यसभा में भाजपा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी से कहा कि सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वंदना चव्हाण ने भी मौसम के इस रुख पर चिंता जताई। शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 रोधी टीकों की एहतियाती खुराक लेने को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने पर चिंता जताई और कहा कि सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं की है। उन्होंने कहा इसके अभाव में विदेश

जाने भारतीयों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई यूरोपीय देशों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में भारत में बूटल खुराक को लेकर एक नीति होनी चाहिए। चतुर्वेदी ने कहा कि देश में हमने वह दौर भी देखा है, जब टीकों की कमी थी और लोग समय पर टीका नहीं लगा पा रहे थे। उन्होंने कहा अब तक टीके भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं लेकिन इसके बावजूद 60 वर्ष से नीचे के लोगों को एहतियाती खुराक देने के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री को एक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी

करना चाहिए, ताकि 60 वर्ष के कम उम्र के लोगों को बूटल खुराक लग सके। द्रविड़ मुनेत्र कणगण (द्रमुक) के तिरुवी शिवा ने विशेष उल्लेख के माध्यम से बच्चों व युवाओं में ऑनलाइन गेम्स के बहते प्रचलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बच्चों व युवाओं में तेजी से यह लत बढ़ रही है और इस खेल में पैसे गंवाने के बाद आत्महत्या करने के मामले भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑनलाइन गेम्स पर देशभर में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भाजपा के अशोक वाजपेयी ने लखनऊ स्थित स्कूटर्स इंडिया

लिमिटेड की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए सरकार से आग्रह किया कि वह इसे इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित कर सकती है। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास पर्याप्त जमीन और अन्य बहुत सारे उपकरण हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जैसे भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में सरकार पीपीपी मोड पर इसका विकास कर सकती है। समाजवादी पार्टी के रेवती रमण सिंह ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दा उठाने और बाजरीकरण से इसका पूरा स्वरूप बदल रहा है।

कोविड से मौत मामले पर सुप्रीम कोर्ट बोला- मुआवजे के दावे के लिए चार हफ्तों का समय नहीं पर्याप्त

नई दिल्ली।

देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के कारण हुई मौत के मामले में प्राधिकारियों से अनुग्रह राशि के भुगतान का दावा करने के लिए के द द्वारा चार हफ्तों की समयसीमा देना संभवतः पर्याप्त नहीं है क्योंकि मृतक के परिवार अपने परिजन को खोने के कारण व्यथित होंगे। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी जी नागरल की पीठ ने संकेत दिया कि ऐसे सभी लोगों को 60 दिन का समय दिया जाएगा जो निर्धारित तिथि से मुआवजे के लिए आवेदन देने के पात्र हैं और भविष्य के दावाकर्ताओं को 60 दिनों का वक्त दिया जाएगा। पीठ ने कहा, 'यह (चार हफ्ते) शायद उचित समय सीमा नहीं है क्योंकि संबंधित परिवार शोकाकुल होंगे और चार हफ्ते का समय शायद सही वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कोविड-19 से मौत के लिए मुआवजे के फर्जी दावों का पता लगाना चाहिए क्योंकि उसे आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत शक्तियां दी गई हैं। फर्जी दावों के सत्यापन के लिए सर्वेक्षण के नमूने देने का अनुरोध करने वाली केंद्र की अर्जा के संबंध में पीठ ने कहा कि यह दो-तीन राज्यों पर केंद्रित हो सकता है, जहां मौत के पंजीकरण और दावों में भ्रमता है। सुनवाई की शुरुआत में केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता ने कोरोना वायरस के कारण हुई मौत पर प्राधिकारियों से मुआवजा मांगने का दावा करने के लिए चार हफ्ते की समयसीमा तय करने का सुझाव दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और वह 23 मार्च को आदेश देगा। चार हफ्ते की समयसीमा तय करने का अनुरोध किया था।

उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को मिलने वाली 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि पाने के लिए झूठे दावों पर चिंता जतायी थी और कहा था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका 'दुरुपयोग' किया जा सकता है और उसे लपटा था कि 'नैतिकता' का स्तर इतना नीचे नहीं गिर सकता।

सेंट्रल स्कूल में सांसदों का कोटा खत्म करने के मुद्दे पर सभी दलों से चर्चा कर निर्णय लेगी सरकार

नई दिल्ली।

लोकसभा में सोमवार को सेंट्रल स्कूलों में जनप्रतिनिधियों के कोटे को लेकर बात उठी। कई सदस्यों ने केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में प्रत्येक सांसद को दिये गए 10 सीटों के कोटे का विषय उठाया और कुछ सांसदों ने मांग की कि कोटे की संख्या को बढ़ाया जाए अन्यथा इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। प्रत्येक सांसद को उसके कोटे की संख्या को बढ़ाया जाए केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 10 सीटों का कोटा मिलता है जिसमें उसकी सिफारिश पर क्षेत्र के किसी विद्यार्थी का इन विद्यालय में दाखिल हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस विषय पर सभी दलों के नेताओं से मंत्री बात करेंगे और फिर कोई अंतिम निर्णय किया

जायेगा। निचले सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के मनीष तिवारी, के सुरेश, तुषारमूल कांग्रेस की महुआ मोडगो सहित कुछ अन्य सदस्यों ने इस विषय को उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि वह समझते हैं कि इस विषय को लेकर जन प्रतिनिधियों पर दबाव है, लेकिन यह कोई अधिकार का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी यह (कोटा) दो सीट का था। जो बाद में पांच सीट का हुआ और अब 10 है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मूल रूप से राज्यों का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की दृष्टि से प्रारंभ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात आई क्योंकि इन कर्मचारियों का तबादला होता रहता है। प्रधान ने कहा कि धीरे धीरे इनका विस्तार हुआ और पिछले 50-60 साल में

देश में केंद्रीय विद्यालय और जाहजर नवोदय विद्यालयों ने प्रतिष्ठ हासिल की। ग्रामीण क्षेत्रों तथा टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में ये अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिये उनका आकर्षण भी है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जनप्रतिनिधियों पर दबाव भी है लेकिन यह समझना होगा कि जन प्रतिनिधि के रूप में सांसदों के तहत लोगों के लिये काम नहीं कर सकते। रूप में सांसद चुनिंदा क्षेत्रों के लिये काम नहीं कर सकते। लिये काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जो बच्चे सांसदों निर्वाचन क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, वे सामान्य वर्ग की प्रक्रिया के तहत पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, 'क्या इस बड़ी पंचायत में बैठकर हमें तय करना है कि क्या हम अपने अधिकार का प्रयोग कुछ चंद लोगों के लिये काम करेंगे

अथवा सभी के लिये काम करेंगे। इस बारे में 'अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन चाहिए।' इस पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों से पूछा कि अगर सभी इस बारे में सहमत हों तब क्या इसे (कोटे) समाप्त कर दिया जाए? उन्होंने कहा कि सरकार ने विशेषाधिकार समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है तब सभी इस पर सहमत हो जाएं। अध्यक्ष ने कहा, 'इस विषय पर सभी दलों के नेताओं से मंत्रीजी बात करेंगे।' बिरला ने कहा कि सभी दलों के नेताओं से बात करके कोई निर्णय किया जायेगा। इससे पहले, इस विषय को उठाते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यहां पर बैठे लोग 15 से 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में 35 से 40 लाख लोग रहते हैं।

सिकंदर कुमार ने सीएम जयराम की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए किया नामांकन

शिमला। भाजपा राज्यसभा प्रत्याशी डॉ सिकंदर कुमार ने विधानसभा में अपना नामांकन कर दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, उपाध्यक्ष हंस राज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। डॉ सिकंदर कुमार विधानसभा प्रातः 10: 20 पर पहुंचे जहां उनका स्वागत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने किया, उसके बाद डॉ सिकंदर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार से उनके कक्ष में मिले, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर सादर भरो की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसी कड़ी में डॉ सिकंदर कुमार ने नामांकन किया है। उन्होंने चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ सिकंदर कुमार पर विचार से हैं और संबंधित करके इस स्थान तक पहुंचे हैं। सिकंदर कुमार अनुसूचित जाति हैं और उन्होंने इस वर्ग के लिए बहुत काम किया है, वह पूर्व में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सिकंदर कुमार अनुसूचित जाति हैं और उन्होंने इस वर्ग के लिए बहुत काम किया है, वह पूर्व में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सिकंदर को इस उपस्थित के लिए सुभकामनाएं दीं और कहा कि उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा नहीं जताई है, बल्कि पार्टी ने स्वयं उनका चयन किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने डॉ सिकंदर कुमार को शुभकामनाएं दीं।

संपादकीय

जापान के साथ

भारत और जापान के बीच बढ़ते संबंधों की जितनी सराहना की जाए कम होगी। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की पहली भारत यात्रा अपेक्षा अनुरूप ही बहुत फलदायी रही है। दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास इनके बीच होने वाले व्यावसायिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, रणनीतिक समझौतों में साफ झलकता है। कुछ ही देश हैं, जिनके प्रति भारतीयों को स्वाभाविक लगाव है, उनमें से एक जापान सबसे अलग है। दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा उम्मीद और लक्ष्य के अनुरूप बढ़ती जा रही है, तो कोई आश्चर्य नहीं। सबसे बड़ी बात कि जापान आगामी पांच वर्षों में भारत में 3.20 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा। वृद्धि साल 2014 में तय लक्ष्य कम्पेन्स हासिल हो चुके हैं, इसलिए भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। दोनों देशों के बीच मोटे तौर पर छह से ज्यादा समझौते हुए हैं। तकनीकी, व्यवसाय, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा इत्यादि के स्तर पर भी भारत को फायदा होने वाला है। यह बहुत खुशी की बात है कि आज भारत में 1,455 जापानी कंपनियां हैं। ग्यारह जापानी औद्योगिक टाउनशिप (जेआईटी) की स्थापना की गई है। जापान विदेशी पूंजी निवेश के मामले में भारत का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत है। भारत-जापान के बीच कोरोना की वजह से पिछले दो वर्षों से उच्चस्तरीय वार्ता एक तरह से रुकी हुई थी और अफ फुमियो किशिदा पहली बार भारत आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में जापान गए थे और उसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों को और बल मिला है। जापान आज एक शांत और सांस्कृतिक रूप से सजग देश है। वह भारत की तरह ही शांति का समर्थक है, उसका भी किसी तरह का साम्राज्यवादी एजेंडा नहीं है। इसलिए दोनों देशों के बीच विशेष लगाव का विस्तार न केवल एशिया, बल्कि विश्व के लिए भी कारगर रहा है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, अनेक मेट्रो परियोजनाएं जापान के सहयोग से बहुत सफलतापूर्वक चल रही हैं। बुनियादी ढांचे में जापान से मिला सहयोग साफ झलकता है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के विकास में भी जापान हमारा बहुत सहयोग कर रहा है। कोशल विकास में भी जापान का बड़ा योगदान है और किसी भी अन्य देश की तुलना में प्रशिक्षण और अनुशासन सिखाने में जापान श्रेष्ठ है। जापान हमें न केवल उदारता से ऋण देता है, हमें विकास करना भी सिखाता है। ऐसे देश के साथ संबंध विस्तार की कोई भी कोशिश स्वागतयोग्य है। भारत को रणनीतिक रूप से भी जापान को संदेश देते रहना चाहिए। जापान विगत कुछ वर्षों से ब्रिक्स की तरफदारी कर रहा है। इसी साल के अंत में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार हो रहा है। यह आयोजन चीन में होना है, जापान चाहता है कि भारत इस सम्मेलन या सहयोग योजना में शामिल हो। लेकिन अब भारत ने यह साफ कर दिया है कि जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझ जाता, तब तक चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि लद्दाख गतिरोध का समाधान नहीं हो पा रहा है। लगता है, चीन ने पिछले सप्ताह हॉट प्रॉग्राम से पीछे हटने की बात कहकर जापानी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार की थी, लेकिन भारत को सावधान रहना चाहिए। पूरे सप्ताह, सहयोग के साथ जापान को साथ रखते हुए अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

आज के कार्टून



ममता

श्रीराम शर्मा आचार्य
संसार से ममता को हटा देने या संसार भर में ममता का विस्तार कर देने का एक ही अर्थ है। यह कि थोड़े ही दायरे में ममता को केंद्रीभूत न रहने दिया जाए वरन उसका उपयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाए। केवल अपने शरीर तक या स्त्री, संतान तक ममता का सीमित रहना पापमूलक है क्योंकि अन्य लोगों को विराना समझने से उनका शोषण करने की प्रवृत्ति बलवती होती है। अपनों के लिए तो त्याग और सेवा करने की इच्छा होगी। अपनी बीमारी को दूर करने के लिए मनमाना पैसा खर्च किया जा सकता है, यदि भाई को अपना मानते हैं, तो उसकी बीमारी में सहायता किए बिना न रहा जाएगा। इस प्रकार पाप-पुण्य की प्रवृत्तियां भी इसी अर्थात् को सिखाते हैं और विस्तार करने पर निर्भर हैं। सदैव उद्योग करते रहिए कि अपना 'अहम्' सीमित न रहे वरन जितना हो सके, विस्तृत किया जाए। आत्मभाव के विस्तार की सूक्ष्म मनोवृत्ति का व्यवहार उदारता में दर्शन किया जा सकता है। जिनके विचार और कार्य उदारतापूर्ण हैं, जो दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हैं, वास्तव में वे इस भूलोक के देवता हैं। अभागा कजूस सोचता है कि सारी दौलत अपने लिए जोड़-जोड़ कर रख लूं, अपनी विधा किसी पर न प्रकट करूं, अपनी शक्तियों को किसी को मुफ्त न दूं, ऐसे लोग सर्प बनकर संपदाओं की चौकीदारी करते हुए मर जाते हैं, उन्हें वह आनंद जीवन भर उपलब्ध नहीं होता जो उदारता द्वारा मिलता है। उदार व्यक्ति पड़ोसी के बच्चों को खिलाकर बिना खर्च उतना ही आनंद प्राप्त कर लेता है जितना कि बहुत खर्च और कष्ट के साथ अपने बालकों को खिलाने में प्राप्त किया जाता है। अपने हसते बालकों को देखकर आपके आपकी छाती गुदगुदाने लगती है। पड़ोसी के उससे भी सुंदर फूल से हंसते हुए बालक को देखकर आपके दिल की कली बूँद नहीं खिलती? अपनी फूलवारी देखकर खुश होते हैं पर पास में ही जो सुरभित उद्यान लहलहाते हैं, वे आप में तरंगें नहीं उत्पन्न करते? आपके आसपास अनेक सदाचारी, कर्तव्यपरायण, मधुर स्वभाव वाले, धर्मात्मा, परोपकारी, विद्वान निवास कर रहे हैं, उनका होना आपको क्यों शांतिदायी नहीं होता? कारण यह कि आप खुद अपने हाथों अपनी एक निजी अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, उसी से संबंध रखना चाहते हैं, उसी की उन्नति देखकर प्रसन्न होना चाहते हैं, ये काम शौतान के हैं। शौतान के कार्य आनंददायक नहीं हो सकते।

जल संकट की गहराती समस्या

(विश्व जल दिवस (22 मार्च) पर विशेष/लेखक-योगेश कुमार गोलय)

जल एक ऐसा दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है, जो सिर्फ कृषि कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है लेकिन चिन्तनीय स्थिति यह है कि जल की कमी का संकट न केवल भारत बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों की एक विकट समस्या बन चुका है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए जल संरक्षण और रखरखाव को लेकर दुनियाभर में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सही मायने में यह दिन जल के महत्व को जानने, समझते रहते जल संरक्षण को लेकर सचेत होने तथा पानी बचाने का संकल्प लेने का दिन है। यह दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1992 में रियो डे जेनेरियो में आयोजित 'पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (यूनिसीडी) में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की इसी घोषणा के बाद पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। दरअसल दुनियाभर में इस समय करीब दो अरब लोग ऐसे हैं, जिन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा और साफ पेयजल उपलब्ध न होने के कारण लाखों लोग बीमार होकर असमय काल का श्रावण बन जाते हैं। बात यदि भारत के संदर्भ में करें तो हमारा देश पहली बार 2011 में जल की कमी वाले देशों की सूची में शामिल हुआ था और अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि महाराष्ट्र हो या राजस्थान, बिहार हो या झारखण्ड या फिर देश की राजधानी दिल्ली, प्रतिवर्ष विशेषकर गर्मी के मौसम में देश के विभिन्न हिस्सों में पानी को लेकर लोगों के बीच आपस में झगड़े-फसाद की खबरें सामने आती रही हैं। कुछ ही साल पहले शिमला जैसे पर्वतीय क्षेत्र में पानी की कमी को लेकर हाहाकार मचा था और उसके अगले साल चेन्नई में वैसी ही स्थिति देखी गई। ये मामले जल संकट गहराने की समस्या को लेकर हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त थे किन्तु फिर भी इससे निपटने के लिए सामुदायिक तौर पर कोई गंभीर प्रयास होते नहीं दिख रहे। यही वजह है कि भारत में बहुत सारे शहर अब

शिमला तथा चेन्नई जैसे हालातों से जूझने के कगार पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में देश के हर ग्रामीण क्षेत्र तक नलों के जरिये प्रत्येक घर में जल पहुंचाए जाने के लिए 'जल जीवन मिशन' नामक अभियान की शुरुआत की गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस मिशन की शुरुआत से पहले देश के ग्रामीण इलाकों में केवल 3.23 करोड़ परिवारों के पास ही नल कनेक्शन थे और इस योजना के तहत 2024 तक 19.22 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पानी पहुंचाए जाने का लक्ष्य है। आंकड़ों के अनुसार इस मिशन की शुरुआत से लेकर 28 महीनों की अवधि में कुल 5.44 करोड़ घरों तक नल से जलापूर्ति शुरू की जा चुकी है और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या कुल 8.67 करोड़ हो चुकी है। हालांकि घर-घर तक जल पहुंचाने का वास्तविक लाभ तभी होगा, जब नलों से जलापूर्ति भी सुचारु रूप से हो और यह केवल तभी संभव होगा, जब जलस्रोतों की बेहतर निगरानी व्यवस्था होने के साथ-साथ जल संरक्षण के लिए कारगर प्रयास नहीं किए जाएं। पृथ्वी का करीब तीन चौथाई हिस्सा पानी से लबालब है लेकिन धरती पर मौजूद पानी के विशाल स्रोत में से महज एक-डेढ़ फीसदी पानी ही ऐसा है, जिसका उपयोग पेयजल या दैनिक क्रियाकलापों के लिए किया जाना संभव है। 'प्रदूषण मुक्त सांसें' पुस्तक में विस्तार से यह वर्णन किया गया है कि पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की कुल मात्रा में से मात्र तीन प्रतिशत पानी ही स्वच्छ बचा है और उसमें से भी करीब दो प्रतिशत पानी पहाड़ों व धरुवों पर बर्फ के रूप में जमा है जबकि शेष एक प्रतिशत पानी का उपयोग ही पेयजल, सिंचाई, कृषि तथा उद्योगों के लिए किया जाता है। बाकी पानी खारा होने अथवा अन्य कारणों की वजह से उपयोगी अथवा जीवनदायी नहीं है। पुस्तक के अनुसार पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में से इस एक प्रतिशत पानी में से भी करीब 95 फीसदी पानी भूमिगत जल के रूप में पृथ्वी की निचली परतों में उपलब्ध है और बाकी पानी पृथ्वी पर सतही जल के रूप में तालाबों, झीलों, नदियों अथवा नहरों में तथा मिट्टी में नमी के रूप में उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि पानी की हमारी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति भूमिगत जल से ही होती है लेकिन इस भूमिगत जल

की मात्रा भी इतनी नहीं है कि इससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। वैसे भी जनसंख्या की रफ्तार तो तेजी से बढ़ रही है किन्तु भूमिगत जलस्तर बढ़ने के बजाय घट रहा है, ऐसे में पानी की कमी का संकट तो गहराना ही है। देश में जल संकट गहराते जाने की प्रमुख वजह है भूमिगत जल का निरन्तर घटता स्तर। एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय दुनिया भर में करीब तीन बिलियन लोगों के समक्ष पानी की समस्या मुंह बाये खड़ी है और विकासशील देशों में तो यह समस्या कुछ ज्यादा ही विकराल होती जा रही है, जहां करीब 95 फीसदी लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। पानी की समस्या एशिया में और खासतौर से भारत में तो बहुत गंभीर रूप धारण कर रही है। विश्वभर में पानी की कमी की समस्या तेजी से उभर रही है और यह भविष्य में बहुत खतरनाक रूप धारण कर सकती है। अधिकांश विशेषज्ञ आशंका जताने लगे हैं कि जिस प्रकार तेल के लिए खाड़ी युद्ध होते रहे हैं, जल संकट बरकरार रहने या और अधिक बढ़ते जाने के कारण आने वाले वर्षों में पानी के लिए भी विभिन्न देशों के बीच युद्ध लड़े जाएंगे और हो सकता है कि अगला विश्व युद्ध भी पानी के मुद्दे को लेकर ही लड़ा जाए। दुनियाभर में पानी की कमी के चलते विभिन्न देशों में और भारत जैसे देश में तो विभिन्न राज्यों में ही जल संधियों पर संकट के बादल मंडराते रहे हैं। बहरहाल, पानी की महत्ता को हमें समझ रहे हैं समझना ही होगा। इस तथ्य से हर कोई परिचित है कि जल ही जीवन है और पानी के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती लेकिन जब हम हर जगह पानी का दुरुपयोग होते देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है। पानी का अंधाधुंध दोहन करने के साथ-साथ हमने नदी, तालाबों, झरनों इत्यादि अपने पारम्परिक जलस्रोतों को भी दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें समझ लेना होगा कि बारिश की एक-एक बूंद बेशकीमती है, जिसे सहेजना बहुत जरूरी है। अगर हम वर्षों के साथ-साथ हमने किए जाने की और खास ध्यान दें तो व्यर्थ बहकर नदियों में जाने वाले पानी का संरक्षण करके उससे पानी की कमी की पूर्ति आसानी से की जा सकती है और इस तरह जल संकट से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

भूजल का दोहन

जल सुरक्षा दिवस विशेष/लेखक-विष्णु अग्रवाल

सदियों पुरानी सभ्यता- भारत, पवित्र नदियों सिंधु और सरस्वती गंगा के तट पर जन्मी और फैली-फूली। प्राचीन ग्रंथों में जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के महत्व को प्रायः रेखांकित किया गया है। 2900 किलोमीटर तक फैली सिंधु नदी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा कृष्णा, महानदी और कावेरी का स्थान आता है। भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। यहां पौधों की 47,000 किस्मों और जानवरों की 89,451 प्रजातियां पाई जाती हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ पानी की बढ़ती मांग के कारण, आज भारत जल क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। 130 करोड़ की वर्तमान जनसंख्या वाले इस देश में पानी की कमी पहले से ही दिखाई दे रही है और 2050 तक आबादी के 160 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है जिससे यह समस्या और भी विकट हो जाएगी। इसके साथ ही बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण विश्वभर में जल चक्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है। भारत की जनसंख्या दुनिया की आबादी का 16 प्रतिशत है, लेकिन यहाँ जल संसाधन दुनिया के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत ही है। भारत में वर्षों से उपलब्ध वार्षिक जल लगभग 4,000 घन कि.मी. है। सतही जल और पुनर्भरणिय उपयोग योग्य भूजल 1,869 घन कि.मी.लेकिन इसका केवल 60 प्रतिशत ही लाभकारी उपयोगों के लिए

रखा जा सकता है, भारत में उपयोग योग्य जल संसाधन केवल 1,122 घन कि.मी. है। हमारे देश में 230 अरब क्यूबिक मीटर भूजल का दोहन हो रहा है। हाल में नीति आयोग के नवीनतम सर्वे के अनुसार भारत में 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। अपर्याप्त प्रदूषित जल के इस्तेमाल की वजह से भारत में हर साल 2 लोगों की मौत हो जाती है। आजादी के बाद देश में 3 राष्ट्रीय जल नीतियां बनीं पहली नीति 1987 में दूसरी 2002 में 2012 में तीसरी जल नीति बनी। जल शक्ति मंत्रालय भित्ति-नीति आयोग द्वारा जारी की गई जल रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि दिल्ली बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद सहित 21 बड़े शहर 2020 तक शुष्क भूजल स्तर तक पहुंचने के कगार पर थे जिससे 100 मिलियन से अधिक लोगों के प्रभावित होने के आसार हैं। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है। कि 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दुगुनी होने का अनुमान है, जिससे करोड़ों लोगों के लिए जल की गंभीर कमी हो सकती है। और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत की हानि हो सकती है। यह माना जाता है कि कृषि भी इस सदी में भूराजनीतिक संघर्ष का एक प्रमुख कारण होगा, कई देशों में जल के बंटवारे तथा जल पर नियंत्रण के लिए भविष्य में युद्ध भी हो सकता है। राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रभावी तरीके से प्रदूषित होने से बचाने और इसके संरक्षण के उद्देश्यों का पूरा करने के लिए जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपये के बजट

परिव्यय के साथ नमामि गंगे फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय गंगा परिषद क अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री है। गंगा सफाई की योजना 2001 से चल रही है आज दिनोंक तक गंगा की सफाई में अरबों रुपये खर्च होने के बाद भी नहीं हो पाई। भ्रष्ट सरकारी तंत्र ने गंगा सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार में दुबकी लगाई। आज भी कानपुर, लखनऊ आदि क्षेत्रों में दूषित नालों का पानी गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। सरकार ने 15 अगस्त 2019 को भारत के 73 वें स्वतंत्रता दिवस पर जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया, ताकि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (हर घर नल जल) को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने के लिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके। 2019-20 के दौरान 7 महीनों में (अगस्त से मार्च तक) 84 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए गए। भारत में पानी की बचत कम और बर्बादी अधिक होती है इसी की वजह से होने वाले जल संकट का ही बड़ा कारण आबादी का बढ़ता दबाव प्रकृति से छेड़छाड़ और कुप्रबंधन भी है। शहरों में पानी खत्म हो जाए और हमारे पास पीने को पानी न बचे। कि कृषि जल एक पुनर्भरणिय संसाधन है। हर साल यह बर्फ और बारिश के रूप में आता है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कृषि को छोड़ कर, हम पानी का पूरी तरह उपभोग नहीं करते रेत वाटर हारवैस्टिंग के द्वारा इसका शोषण कर इसे फिर इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है। इस तरह, इस क्षेत्र में हम भविष्य को

बदल सकते हैं। शहरो व गाँव के प्राचीन कुयें व तालाबों को विकास की दौड़ में भ्रष्ट सरकारी तंत्र ने तालाबों की जगहो पर अवैध कब्जा हो गया। तथा कुओं को नगर पालिका, नगर निगम द्वारा शहर का कचड़ा एकट्टा कर कुओं में डालकर बन्द कर दिया गया है। कुओं को हमारी भ्रष्ट व्यवस्था ने डसबीन बना दिया है। जल जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। यह एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है। भारत में दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत से अधिक है, जबकि इसके पास नदीकणीय जल संसाधन विश्वभर के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत ही है। भारत में 3,880 बिलियन घन मीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है। लेकिन समय और स्थान दोनों दृष्टियों से इसमें अत्यधिक भिन्नता है। कहीं-कहीं 50 प्रतिशत से अधिक वर्षा लगभग 15 दिनों में होती है और कई स्थानों पर एक वर्ष में 100 घंटे से कम वर्षा होती है। वाष्पीकरण के बाद, यहा लगभग 2,000 बिलियन घन मीटर पानी की विलय पाता है। भूवैज्ञानिक और अन्य कारकों की वजह से इस मात्रा का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। उपयोग किया जाने वाला जल लगभग 78 प्रतिशत जल कृषि के लिए 6 प्रतिशत घरेलू उपयोग के लिए 6 प्रतिशत उद्योगों के लिए और शेष 8 प्रतिशत अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन में हाल के वर्षों में एक बदलाव देखा गया है। क्योंकि देश के विकास के एजेंडे में जल शासन को सबसे आगे रखा गया है।

सू-दोक् नवताल -2074

		2		3	
		9	8	2	6
1		3	6	9	
4	3				
	8		2		1
				8	6
	4	7	5		3
3	7	5	4	1	
	2			8	

सू-दोक् -2073 का हल

3	9	7	2	6	5	8	4	1
6	4	2	8	1	9	5	3	7
8	1	5	4	7	3	6	9	2
9	5	8	7	4	1	3	2	6
1	2	3	9	5	6	7	8	4
4	7	6	3	8	2	9	1	5
7	8	1	6	9	4	2	5	3
2	6	4	5	3	8	1	7	9
5	3	9	1	2	7	4	6	8

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3 x 3 के वर्ग में किसी भी अंक को पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।

बारें से दायें:-

1. अनिल, अक्षय, मनोज, करीना, शर्मिला को फिल्म-3
20. 'आते जाते हुए' गीत वाली अमिताभ, शशिधर, राखी, परवीन को फिल्म-2
21. राजकुमार, धर्मेन्द्र, मोनाकुमारी को 'तोर मन दर्पण' गीत वाली फिल्म-3
23. 'आज हमने दिल' गीत वाली नसीर, अतुलअग्निहोत्री, पूजाभट्ट को फिल्म-2
24. गुरुलक्ष्मी, पूजा भट्ट को 'जो प्यार कर गये' गीत वाली फिल्म-3
25. 'साल के बाग महीने' गीत वाली कुमारी गौरव, माधुरी को फिल्म-2
26. संजीवकुमार, शर्मिला को 1974 को कृष्णन पंडु निर्देशित एक फिल्म-4
29. 'पति पत्नी और वो' में संजीवकुमार के साथ नायिका कीन थी-2
30. 'बया चीज है मुहब्बत' गीत वाली सुनील शेट्टी, दिव्या को फिल्म-4

फिल्म वर्ग पहली-2073

बा	रु	द	र	ख	ला	या	जी
कु	सा	च	ज	ज	प		
ल	ली	र	रु	ल	व्य	ह	
म	दा	मि	जी	अ	ल		
जी	त	मा	य	ती	म	ब	
नि	कु	द	र	त	ल	सि	ल
मि	ली	ज	ज	जी	म	त	
जी	सा	सु	जी	ल	म	ज	
के	ला	जं	जा	की	सी		
रु	री	अं	बा	का	रु	ज	ब

1. 'जब ना माना दिल' गीत वाली फिल्म-3
2. कुलभूषण, जावेद, शबाना, नंदिता दास को एक फिल्म-3
3. 'नागिन सा रूप है तेरा' गीत वाली धर्मेन्द्र, हेमा, रीना राय को फिल्म-4
5. अमिताभ, वहीदा, जीतन को एक फिल्म-3
6. 'पहलान मेरे दिल पे तुम्हारा' गीत वाली सुनीलदात, साधना को फिल्म-3
9. अर्जुन रामपाल, जावेदखान, अमीषा को 'उड़ उड़ उड़ जाये' गीत वाली फिल्म-2
10. 'वो कागज की कसती' गीत वाली कुमारी गौरव, आनिका पाल को फिल्म-2
11. 'खुशना भी नहीं आता' गीत वाली फिल्म-4

फिल्म वर्ग पहली-2074

1	2	3	4	5	6
	7				
8	9		10		11
	12		13		
	14	15		16	
17		18		19	
	20		21		22
	23		24		25
26		27		28	
	29		30		

ऊपर से नीचे:-

12. अजय देवगन, करिश्मा कपूर को फिल्म-4
13. जितेंद्र, कमल सदाना, आयशा, दिव्या को 'तेरी मुहब्बत नै दिल में' गीत वाली फिल्म-2
14. 'जिस दिल में बसा था प्यार तेरा' गीत वाली प्रदीपकुमार, कल्पना को फिल्म-3
16. 'दो प्यार करने वाले' गीत वाली फिल्म-3
19. संजयदत्त, सलमान, माधुरी को फिल्म-3
20. राजकुमार मोनाकुमारी को 'ए चांद जहाँ वो जाये' गीत वाली फिल्म-3
21. 'जेक एण्ड जिल' गीत वाली अजय, उर्मिला को फिल्म-3
22. 'मैंने प्यार किया' में नायक कीन था-4
23. 'आँखों में नंदी ना दिल में' गीत वाली संजयदत्त, मनीषा को फिल्म-3
27. फिल्म 'नीलकण्ठ' के संगीतकार कौन थे-2
28. 'दिलवालों के दिल का करार लूटने' गीत वाली फिल्म-2

ब्रेंट क्रूड वायदा 1.96 डॉलर चढ़कर 109.89 डॉलर प्रति बैरल पहुंचा



वॉशिंगटन ।

कच्चे तेल की कीमतों में सोमवार को 2 डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई है क्योंकि यूक्रेनी सेना ने रूसी हमलों के खिलाफ रक्षात्मक स्थिति अपनाई और वहीं दूसरी ओर प्रमुख तेल उत्पादकों ने बताया कि वह आपूर्ति समझौते के तहत अपने आवंटित कोटा का उत्पादन

करने के लिए संवर्ध कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड वायदा 1.96 डॉलर या 1.8 फीसदी चढ़कर 109.89 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। इसमें शुक्रवार को भी 1.2 फीसदी की वृद्धि हुई थी। यूएस वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड प्यूचर्स 2 फीसदी बढ़कर 106.79 डॉलर हो गया। इसमें भी बोते शुक्रवार को 1.7 प्रतिशत की तेजी देखी गई थी। कीमतों में बढ़ोतरी तब हुई जब सोमवार सुबह यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री इरिना वरेश्चुक ने कहा कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि देश की सेना पूर्वी बंदरगाह वाले

शहर मरियो पोल में आत्मसमर्पण करेगी। एएनजेड के विश्लेषकों ने कहा कि बाजार आपूर्ति में व्यवधान के बारे में चिंतित है, डेटा के अनुसार वह पहले से ही प्रभावित हो रहा है। रूस सहित पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगियों (ओपेक प्लस) की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ उत्पादक अभी भी अपने सहमत आपूर्ति कोटा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ओपेक प्लस देशों का फरवरी में अपने उत्पादन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। इसमें एक मिलियन बैरल प्रति दिन (बीपीडी) से अधिक की कमी रही। तीन सूचों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी।

उन्हें समझौते के तहत हर महीने 400,000 बीपीडी उत्पादन को बढ़ावा देना था क्योंकि इससे पहले वह 2020 में कटौती कर चुके थे और अब उसकी भरपाई करनी थी। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने अब तक प्रमुख उपभोक्ता देशों द्वारा तेल की कीमतों को कम करने में मदद के लिए उत्पादन में तेजी लाने के आह्वान का विरोध किया है। कम आपूर्ति और उच्च कीमतों ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को चार महीनों के भीतर तेल के उपयोग में 2.7 मिलियन बीपीडी की कटौती करने के तयों की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रेरित किया।

लोकल एजेंट अब कनाडा के लिए एयर इंडिया की टिकट बुक नहीं कर सकेंगे

नई दिल्ली ।

एयर इंडिया ने लोकल एजेंट्स के कनाडा सेक्टर के लिए टिकट बुक करने पर रोक लगा दी है। दो साल के प्रे तिबंध पाबंदी के बाद अब इंटरनेशनल ट्रेवल में छूट दी गई है जिससे मांग बढ़ गई है। जानकारों के मुताबिक लोकल एजेंट्स इस पर जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। इसे रोकने के लिए

एयर इंडिया ने यह फैसला लिया है। ट्रेवल इंस्ट्रुमेंट के एक वर्ग का मानना है कि एयरलाइन की यह सख्त कार्रवाई उसके नए मालिक टाटा ग्रुप की वैल्यू को दिखाता है। एयर इंडिया को इस बात की जानकारी मिली थी कि कुछ लोकल एजेंट टिकटों की बिक्री में उचित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए कंपनी ने उनके टिकट बुक करने पर प्रे तिबंध

लगा दिया। जानकारी के मुताबिक इन एजेंटों में बड़ा घालमेल किया था। वे एक तय कीमत पर सीटें ब्लॉक कर रहे थे और उससे चार गुना कीमत पर बेच रहे थे। इसी कारण उन पर रोक लगाई गई है क्योंकि इससे एयरलाइन को भारी नुकसान हो रहा था। अब कनाडा सेक्टर पर यात्रा करने जा रहे यात्री सीधे एयरलाइन की वेबसाइट पर टिकट बुक कर सकते हैं। पेंसेंजर

अब कॉल सेंटर्स और एयरलाइन की वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। इस बारे में एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि वह इस बारे में संबंधित विभाग से जवाब का इंतजार है। लेकिन एजेंट्स पर प्रे तिबंध से गर्मियों की छुट्टियों के पीक सीजन में एयर इंडिया की कनाडा के लिए टिकटों की बुकिंग प्रभावित हो सकती है।

रिलायंस रिटेल ने लॉन्गरी ब्रांड रिटेलर क्लोविया में खरीदी 89 फीसदी हिस्सेदारी



नई दिल्ली ।

रिलायंस रिटेल वेंचर्स (आरआरवी) ने जिवाम और अमाटे के बाद अब ऑनलाइन लॉन्गरी रिटेलर क्लोविया में 89 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी ने 950 करोड़ रुपए के सौदे में यह हिस्सेदारी हासिल की है। कंपनी ने बताया कि इस सौदे में प्राथमिक निवेश और रिक्रियल शेयर बिक्री शामिल है। रिलायंस

रिटेल वेंचर्स ने बयान में कहा कि क्लोविया की संस्थापक टीम और प्रबंधन कंपनी की बाकी हिस्सेदारी का मालिक होगा। कंपनी ने कहा कि पंकज वर्मानी, नेहा कांत और सुमन चौधरी द्वारा साल 2013 में क्लोविया की शुरुआत की गई थी। क्लोविया 3,500 से अधिक उत्पाद शैलियों की पेशकश करती है। इससे पहले रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने बंगलुरु स्थित फर्म डुजो में 25 फीसदी हिस्सेदारी लेने के लिए 240 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। इस सौदे पर रिलायंस रिटेल क्लैट और रिटेल एक्सपर्टीज का फायदा मिलेगा।

विकल्पों को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम मूल्य प्रस्ताव पेश करने में सबसे आगे रहा है। हमें अपने पोर्टफोलियो में स्ट्राइल, गुणवत्ता और डिजाइन आधारित इंटिग्रेट वियर ब्रांड क्लोविया को शामिल करते हुए खुशी हो रही है। हम व्यवसाय को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्लोविया में मजबूत प्रबंधन टीम के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। वहीं क्लोविया के संस्थापक और सीईओ पंकज वर्मानी ने कहा कि क्लोविया रिलायंस रिटेल परिवार का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित है। इस साझेदारी से हमें रिलायंस की स्कैल और रिटेल एक्सपर्टीज का फायदा मिलेगा।

भारत में 23 को लांच होगा स्मार्टफोन ओप्यो के-10, मिलेगा दमदार बैटरी का सपोर्ट

नई दिल्ली ।

ओप्यो के-10 भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। फोन को भारत में 23 मार्च को लॉन्च किया जाएगा, लॉन्चिंग से पहले फोन के कई खास फीचर्स लीक हो गए हैं। यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आएगा। इस चीनी फोन बनाने वाली कंपनी ने बताया कि ये मिड-रेंज फोन होगा, और इसे बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। ओप्यो के-10, रैम एक्सटेंशन टेकनोलॉजी के साथ आएगा, और ये इस सीरीज का पहला फोन होगा। ओप्यो के-10 पिताकॉर्ट के लिए 23 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने पहले ही नोटिफाई भी पेंज को

लाइव कर दिया है। ओप्यो के-10 के साथ-साथ कंपनी टीडब्ल्यूएस इन्को एयर-2 को भी पेश करेगा। ओप्यो के-10 को माइक्रो पेज पर दो कलर वेरिएंट में देखा गया है। ये 6एनएम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर के साथ आता है। आने वाले ओप्यो के-10 पंच होल डिस्प्ले डिजाइन दी गई है, जो कि सेल्फी लेंस के साथ आता है। ओप्यो के-10 को लेकर कहा जा रहा है कि ये बजट सेगमेंट का फोन होगा, और इसके लिए इसे फीचर्स भी ऐसे ही होंगे। उदाहरण के तौर पर ओप्यो के-10 में 5,000एमएच की बैटरी दी जा सकती है, जो कि 18वाट चार्जर के साथ आएगी। उम्मीद की जा रही है कि यह एन्ड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आएगा।

ओप्यो के-10 में कम से कम 3जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है। कम से कम 3जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है। हालांकि ओप्यो ने एसी कोई जानकारी नहीं दी है। लोक रिपोर्ट के मुताबिक ओप्यो के-10 को भारत में 20,000 रुपए से कम कीमत में पेश किया जा सकता है। हालांकि ओप्यो ने एसी कोई जानकारी नहीं दी है। ओप्यो के-10 के अलावा व्हेट में ओप्यो टीडब्ल्यूएस, एन्को एयर2 में 13.4 एमएम का डायनेमिक ड्राइवर और तीन इन्कलाइज मोड्स मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि ये 24 घंटे के प्लेबैक टाइम के साथ आता है।

संक्षिप्त समाचार



स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप के बढ़ सकते हैं दाम

नई दिल्ली । कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों का असर स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते चीन के कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। चीन के टेक हब शेनझेन क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों में ताजा उछाल के बाद लॉकडाउन से टीवी, लैपटॉप और स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। इंटरनेशनल डेटा कार्पोरेशन के मुताबिक भारत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति का लगभग 20 से 50 फीसदी तक चीन के शेनझेन से आता है। अगर कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन जैसे हालात फिर से पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से इसका असर तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर देखने को मिलेगा। उत्पादों की लागत बढ़ रही है और बढ़ती कीमतों का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अगर शेनझेन शहर में लॉकडाउन तीन सप्ताह या उससे अधिक के पाए जाता है, तो यह जून तिमाही के साथ-साथ स्तित्वर तिमाही में स्मार्टफोन और पर्सनल कंप्यूटर के शिपमेंट को प्रभावित करेगा। काउंटरपॉइंट रिसर्च के एक शोधकर्ता ने कहा है कि अगर लॉकडाउन 20 मार्च से आगे बढ़ता है तो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। स्मार्टफोन की कीमतें 5-7 फीसदी तक बढ़ सकती हैं। बाजार के जानकार कहते हैं कि उत्पादों की कीमत और माल ढुआई दरें पिछले एक साल में बढ़ी हैं, जिसका अर्थ है कि अधिकांश ब्रांड नई लागत के दबाव को सहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और वे इस दबाव को उपभोक्ताओं के ऊपर डाल देंगे। विश्लेषकों का कहना है कि एप्पल को छोड़कर अधिकांश स्मार्टफोन ब्रांड 2-3 फीसदी के मामूली मुनाफे पर काम करते हैं।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने पुणे टाउनशिप में 1,002 करोड़ के घर बेचे

नई दिल्ली । गोदरेज प्रॉपर्टीज ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित टाउनशिप में चालू वित्त वर्ष में अब तक 1,002 करोड़ रुपए के घर बेचे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड (जीपीएल) ने सोमवार को शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा कि पुणे के महालुंगे में टाउनशिप परियोजना रिवरहिल्स में चालू वित्त वर्ष में 1,002 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में इस टाउनशिप परियोजना में 1,550 से अधिक घर बेचे हैं जो 15 लाख वर्गफुट क्षेत्र में फैले हैं। टाउनशिप के पहले चरण की शुरुआत 2019 में हुई थी तब से जीपीएल ने 3,600 से अधिक घर बेचे हैं जो 34 लाख वर्गफुट क्षेत्र में फैले हैं और इनका बुकिंग मूल्य 2,100 करोड़ रुपए से अधिक है।

कोरोना की दवा के लिए स्ट्राइड्स फार्मा का मेडिसीन्स पेटेंट पूल से करार

नई दिल्ली । स्ट्राइड्स फार्मा साइंस ने सोमवार को कहा कि फाइजर की ओरल (खाई जाने वाली) कोविड-19 दवा के जेनेरिक संस्करण के 95 निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में वार्णिज्यकरण के लिए उसने मेडिसीन्स पेटेंट पूल (एमपीपी) के साथ उप-लाइसेंस समझौता किया है। अमेरिका तथा अन्य देशों में उच्च जोरिडम में आने वाले व्यक्तों और रोगग्रस्त बच्चों के लिए फाइजर के इस उत्पाद के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इस दवा को खाना जा सकता है। कंपनी ने कहा कि एमपीपी के साथ उप-लाइसेंस समझौते के तहत कोविडैक्स नाम की दवा को 95 बाजारों में उतारा जाएगा। इसका विनिर्माण कंपनी के बंगलुरु स्थित संयंत्र में किया जाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा साइंस के संस्थापक अरुण कुमार ने कहा कि यह दुनियाभर में कोविड-19 के खतरे से लड़ने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के उत्पादन की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

सिंटेक्स के कर्जदाताओं ने रिलायंस, एसीआरडी की संयुक्त समाधान प्रक्रिया को मंजूरी दी

नई दिल्ली । कर्ज संकट से जूझ रही टेक्सटाइल निर्माता सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के कर्जदाताओं ने दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत इस कंपनी के अधिग्रहण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज (एसीआरडी) की संयुक्त बोली को मंजूरी दे दी है। शेयर बाजारों को मिली जानकारी के अनुसार सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसीआरडी की संयुक्त समाधान योजना के पक्ष में आम सहमति से मतदान किया। इसमें बताया गया कि समाधान योजना को मंजूरी के लिए ई-मतदान की प्रक्रिया 19 मार्च को पूरी हुई और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा एसीआरडी की संयुक्त समाधान योजना को सीओसी के सभी सदस्यों ने मंजूरी दी। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज ने संयुक्त बोली की राशि का खुलासा नहीं किया है लेकिन कुछ मॉडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बोली की राशि लगभग 3,000 करोड़ रुपए है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के समाधान पेशेवर को वेल्समन समूह की फर्म ईजीगो टेक्सटाइल्स, जीएचसीएल और हिम्मतसिंगका वेंचर्स के साथ श्रीकांत हिम्मतसिंगका और दिनेश कुमार हिम्मतसिंगका की बोलियां भी मिली थीं कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू हुई थी।

बीएसएनएल को 2021-22 में विभिन्न सेवाओं से आय 17,000 करोड़ रहने की उम्मीद

नई दिल्ली ।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने बताया कि कंपनी को 2021-22 में 17,000 करोड़ रुपये की सेवा से आय होने की उम्मीद है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में थोड़ी कम है। उन्होंने बताया कि कॉल कनेक्ट शुल्क हटाने के कारण मुख्य रूप से आय में कमी आएगी। पुरवार ने कहा सरकार कंपनी को अपना ग्राहक आधार बनाए

रखने और आने वाले महीनों में शुरू होने वाली 4जी सेवाओं से अपनी पकड़ बनाए रखने का भरपूर है। उन्होंने कहा 5जी सेवाओं के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों की प्रतिस्पर्धा तेज होने के बावजूद ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि निजी परिचालकों द्वारा 5जी पेशकशों की शुरुआत से बीएसएनएल को तत्कालीन नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नए जमाने की सेवाओं के लिए उपकरण अभी विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवाएं शुरू करने की

तैयारी अच्छी तरह से चल रही है। बीएसएनएल का 2022 में 4जी सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। पुरवार ने बताया कि हम चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2021-22 में स्थिर आय (सेवाओं से, अन्य आय को छोड़कर) को बनाए रखने में सक्षम हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में सेवाओं से 17,452 करोड़ रुपये की आय के मुकाबले, इस साल हम 17,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरकनेक्ट उपयोग



शुल्क को हटाने के कारण आय में कमी हुई है। बीएसएनएल का घाटा 2019-20 में 15,500 करोड़ रुपये था, जो 2020-21 में घटकर 7,441 करोड़ रुपए रह गया था। बीएसएनएल प्रमुख ने कहा हमें चालू वित्त वर्ष में पिछले साल की तरह ही नुकसान की आशंका है।

थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल दामों में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी

नई दिल्ली ।

महंगाई के उछाल का असर डीजल पर भी पड़ने वाला है। अब थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि थोक ग्राहकों को बिक्री वाला डीजल 25 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40 प्रतिशत के उछाल के बाद यह कदम उठाया गया है। हालांकि, पेट्रोल पंपों के जरिये बेचे जाने वाले डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस महीने पेट्रोल पंपों की बिक्री में 20 प्रतिशत का उछाल आया है। बस बेड़े के परिचालकों और माल

जैसे थोक उपभोक्ताओं ने पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदा है। आमतौर पर वे पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे ईंधन की खरीद करते हैं। इससे ईंधन की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनियों का नुकसान बढ़ा है। सबसे अधिक प्रभावित नायरा एनजी, जिन्को-बीपी और शेल जैसे कंपनियां हुई हैं। बिक्री बढ़ने के बावजूद इन कंपनियों ने अभी तक मात्रा में कमी नहीं की है। लेकिन आम पंपों के लिए परिचालन आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं रह जाएगा। मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने कहा कि रिफाई 136 दिन से ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से कंपनियों के लिए इन दरों पर अधिक ईंधन बेचने के बजाय

पेट्रोल पंपों को बंद करना अधिक व्यावहारिक विकल्प होगा। वर्ष 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिक्री घटक 'शुल्क' पर आने के बाद अपने सभी 1,432 पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे। सूत्रों ने कहा कि कुछ यहीं स्थिति आज भी बन रही है। थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से खरीदारी कर रहे हैं। इससे इन रिटेलरों का घाटा बढ़ रहा है। मुंबई में थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल का दाम बढ़कर 122.05 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल पंपों पर डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर के भाव बिक रहा है। इसी तरह दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर है जबकि थोक या औद्योगिक ग्राहकों के लिए इसकी कीमत 115 रुपये प्रति

लीटर है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने चार नवंबर, 2021 से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। हालांकि, इस दौरान वैश्विक स्तर पर ईंधन कीमतों में उछाल आया है। माना जा रहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की वजह से फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। थोक उपभोक्ताओं के लिए दरों और पेट्रोल पंप कीमतों में 25 रुपये के बड़े अंतर की वजह से थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे हैं।

मारुति बलेनो-टोयोटा ग्लैंजा आ रही सीएनजी अवतार में

नई दिल्ली । बोते दिनों लॉन्च 2022 नई मारुति बलेनो और नई टोयोटा ग्लैंजा भी जल्द सीएनजी अवतार में आने वाली हैं। दोनों ही कारें प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की हैं और मारुति सुजुकी-टोयोटा पार्टनरशिप के तहत तैयार हुई हैं। बोते दिनों ही ये दोनों मॉडल अपडेट हुई हैं, जिनमें लुक तो बेहतर किया ही गया है, साथ ही डेर सारे नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। फिलहाल ये दोनों ही कारें पेट्रोल इंजन ऑप्शन में हैं और जल्द ही इनके सीएनजी वेरिएंट्स भी आने वाले हैं, जिससे लोगों की जेब पर बोझ कम होगा और उनके पैसे बचेगे। आजकल जब पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, ऐसे में लोग नई कार खरीदने से पहले ये जानना चाहते हैं कि यह माइलेज कितना देती है। आप नई बलेनो और नई ग्लैंजा के अपकॉमिंग सीएनजी मॉडल की माइलेज के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे। ऐसे में आपको बता दें कि टोयोटा ग्लैंजा की वेबसाइट के मुताबिक नई ग्लैंजा सीएनजी को 25केएमपीएल तक की माइलेज के साथ पेश किया जाएगा। वहीं, नई मारुति बलेनो की माइलेज भी 25केएमपीएल से 30केएमपीएल तक के बीच हो सकती है। फिलहाल इन दोनों हैचबैक के रेगुलर मॉडल में 1.2 लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन लगा है, जो कि म्यूअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रान्समिशन ऑप्शन में है। इन कारों के पेट्रोल इंजन ऑप्शन की माइलेज 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक की है। बता दें कि नई टोयोटा ग्लैंजा को भारत में ई.एस.जी और वी जैसे टिम लेवल के डेर सारे वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिनकी कीमतें 6.4 लाख रुपये से लेकर 9.7 लाख रुपये (एक्स शोर्कम) तक है। वहीं, नई मारुति बलेनो की कीमत 6.35 लाख रुपये से लेकर 9.49 लाख रुपये (एक्स शोर्कम) तक है।

20 बिलियन डॉलर का उत्पादन करेगा आईफोन एसई



सैन फ्रांसिस्को ।

एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, विश्लेषक अमित दरयानी ने मुख्य रूप से आईफोन एसई (2022)

द्वारा संचालित एप्पल प्रोडक्ट्स के शिपमेंट और बिक्री में वृद्धि की भविष्यवाणी की है, जिसे आधिकारिक तौर पर कुछ दिन पहले अनावरण किया गया था। नया आईफोन एसई (2022) अपने पहले साल में 20 बिलियन डॉलर का उत्पादन कर सकता है। बजट आईफोन एसई प्रोडक्ट का तीसरा संस्करण है और इसकी कीमत 400 डॉलर

से ठीक ऊपर है, जबकि यह कई प्रीमियम-ग्रेड सुविधाओं के साथ आता है। दरयानी ने कहा कि आईफोन एसई 3 लॉन्च अपने पहले साल के भीतर मॉडल की 35 मिलियन यूनिट के शिपमेंट को पार करने के लिए बहुत जरूरी टेलिविड प्रदान करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रेषण कुछ प्रमुख बुनियादी बातों से प्रेरित है जो संकेत देते हैं कि लैटेंट आईफोन एसई पारंपरिक पुराने आईफोन यूजर्स को बजट के

अनुकूल स्मार्टफोन की ओर आकर्षित करेगा। अपनी 5जी क्षमता के अलावा, आईफोन एसई 3 एप्पल के प्रीमियम ए15 बायोमेट्रिक चिप द्वारा संचालित है, जो आईफोन 13 सीरीज में भी मौजूद है। दरयानी आईफोन एसई 3 को इसके साथ आने वाली सुविधाओं के लिए अच्छी कीमत के रूप में देखता है, इस तथ्य के साथ कि यह आईफोन 8 जैसे कुछ पुराने आईफोन मॉडल के साथ-साथ इसकी 5जी क्षमताओं को भी

बेहतर बनाता है। शिपमेंट लागत के साथ भी, नया आईफोन एसई 3 450 डॉलर से 500 डॉलर के आसपास मंडराएगा और यह ब्यूफर्टिनो-आधारित तकनीकी दिग्गज के लिए वार्षिक राजस्व में 20 बिलियन डॉलर तक का उत्पादन कर सकता है। आईफोन एसई 3 की बेची गई इकाइयों की मात्रा 2022 के अंत तक एप्पल के राजस्व अनुमानों का 5 प्रतिशत तक हो सकती है, जो प्रभावशाली है।

जापान की कंपनी लेक्सस भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उतारेगी

नई दिल्ली । भारत में विकास के अगले चरण की ओर बढ़ रही लज्जरी कार कंपनी लेक्सस अब यहां के बाजार में अपने बिक्री नेटवर्क को मजबूत करने और इलेक्ट्रिक कारों समेत नए मॉडल बाजार में उतारने की तैयारी पर विचार कर रही है। कंपनी के एक वे रिश अधिकारी ने यह जानकारी दी। जापान की कार विनिर्माता कंपनी टोयोटा की लज्जरी कार इकाई लेक्सस ने भारत में परिचालन 2017 में शुरू किया था और अभी यह देश में सात कार मॉडल बेचती है जिनमें स्थानीय स्तर पर विनिर्मित एस 300 एच सेडान भी शामिल है। स्वतंत्र चार्ज होने वाली अपनी हाइब्रिड कारों के लिए पहचानी जाने वाली लेक्सस बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखने की तैयारी कर रही है। लेक्सस इंडिया के एक वे रिश अधिकारी ने कहा कि अभी कार मॉडल यूएक्स का पूर्ण बैटरी इलेक्ट्रिक रूप में भारतीय जलवायु परिस्थितियों के हिसाब से आकलन किया जा रहा है। परीक्षण में विशेषकर गर्मी और धूल के बैटरी पर असर का पता लगाने के बाद कंपनी देश में इस मॉडल को उतारने के बारे में गंभीरता से विचार कर सकती है। भविष्य में चार्जिंग अवसरों के विकास के साथ कंपनी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए और भी तैयार होगी।



हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियों के परिवारों की सामूहिक शक्ति को आजादी का अमृत महोत्सव में एक जुट करें : पीएम मोदी



अहमदाबाद। साथ, सबका विकास, सबका अहमदाबाद के सरखेज-विश्वास' के सूत्र के मूल में पूज्य गांधीनगर राजमार्ग पर स्थित शास्त्रीजी-स्वामी धर्मजीवनदासजी एसजीवीपी गुरुकुल में आयोजित के विचार शामिल है। इस अवसर भाववन्दना पर्व को संबोधित करते पर स्वामी श्री माधवप्रियदासजी हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा लिखित 'धर्म जीवन गाथा' ग्रंथ का कि उनके द्वारा दिया गया 'सबका विमोचन के असवर पर भारी भौड़

SGVP में 'धर्मजीवन गाथा' ग्रंथ के विमोचन कार्यक्रम में मोदी रहें वर्चुअली उपस्थित, पटेल हुए सहभागी

को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर स्वामी श्री माधवप्रियदासजी पुनः स्थापित कर हम 'श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस असवर पर समाज को व्यवसमुक्त बनाने में स्वामिनारायण संप्रदाय द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, अहमदाबाद शहर के महापौर किरीट परमार, कृषि मंत्री राधवजी पटेल, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डी. एन. पटेल तथा स्वामिनारायण संप्रदाय के संत तथा विशाल संख्या में हरिभक्त उपस्थित थे।

नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपी 10 दिन की पुलिस रिमांड पर कच्छ।

चार अलग अलग टीमों बनाकर भुज के भुजिया डुंगर की हुसैन ककल, राहुल सधवारा, तलहटी में नाबालिग लड़की से किशन देवीपूजक और महेश सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में महेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चार आरोपियों को पीडित किशोरी के मुताबिक गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष गत 16 मार्च को वालजी उर्फ पेश कर रिमांड की मांग की थी। किशन उसे बहला-फुसलाकर कोर्ट ने चारों को आरोपियों की भुजिया डुंगर के निकट एक 10 दिन की रिमांड मंजूर की है। जहां पहले सामूहिक दुष्कर्म की घटना उस समय सामने आई जब नाबालिग लड़की अर्धनग्न और एक युवक उसे नशायुक्त पेय पिलाया गया, गन्गनास्था और बेहोशी की हालत जिससे वह बेहोश हो गई। चारों में कच्छ जिले के भुज तहसील के भुजिया डुंगर तलहटी में मिले गए आरोपियों की मेडिकल जांच कराने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने सभी चार आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। जिसके आधार पर पुलिस ने है।

कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने हेल्थकेयर पर आधारित सी.एस.आर. प्रॉजेक्ट के तहत सूरत के नए सिविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस प्रदान की



सूरत। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ("के.एम.बी.एल." / "बैंक") ने आज यह घोषणा की कि सूरत और आसपास के जिलों में समाज के विभिन्न भागों के लोगों को चिकित्सा सेवाओं की बेहतर और समय पर पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वह सूरत (गुजरात) के न्यू सिविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को एक एम्बुलेंस प्रदान कर रहा है।

कोटक महिंद्रा बैंक के हेल्थकेयर पर आधारित सी.एस.आर. प्रॉजेक्ट के तहत प्रदान की गई एम्बुलेंस चिकित्सा सुविधाओं के लिए समय पर और सुगम पहुंच प्रदान करने और स्थानीय लोगों, प्रधानतः निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोगों की चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्णतः सुसज्जित है।

विराट दीवानजी, ग्रुप अध्यक्ष - रिटेल लायबिलिटीज एंड ब्रांच बैंकिंग और ग्रुप मैनेजमेंट कार्डिनल के सदस्य, कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा, "एम्बुलेंस जिंदगियाँ बचाने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है और नए सिविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के संचालन की व्यापकता और स्तर को देखते हुए, आपातकालीन सहायता की आवश्यकता

'आप' ने दो दिग्गज नेताओं को सौंपी गुजरात की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

अहमदाबाद। है और इन राज्यों में लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी है। आप अब असम से तेलंगाणा तक चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। गुजरात की जिम्मेदारी संदीप पाठक को सौंपी गई है, जिन्हें आप पंजाब से राज्यसभा भेज रही है। पंजाब विधानसभा के चुनाव में आप ने शानदार जीत दर्ज कर सरकार बना ली है और इस जीत का श्रेय प्रो. संदीप पाठक को दिया जा रहा है। संदीप पाठक आईआईटी-दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए संदीप पाठक आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। संदीप पाठक ने 2011 में केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी (यूके) में पीएचडी



की थी, जिसके बाद कई सालों तक वह पढ़ने के पीछे रहकर काम करते रहे।

संदीप पाठक ने पंजाब में आप के संगठन को मजबूत किया। राज्य में वास्तविक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण, उम्मीदवारों के चयन समेत पंजाब में पार्टी की शानदार जीत की पूरी रणनीति में संदीप पाठक की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। अब देखा होगा कि आप के गुजरात प्रभारी संदीप पाठक गुजरात विधानसभा के चुनाव पार्टी को कितनी सफलता दिला पाते हैं। आप ने गुजरात में वास्तविक और वैज्ञानिक हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम तेलंगाणा और केरल समेत 9 राज्यों विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

प्रेमिका की हत्या के बाद आत्महत्या का प्रयास करनेवाले युवक की अस्पताल में मौत

राजकोट। था। पुलिस की प्रारंभिक जांच दिन उसके शव के पास बैठा रहा और सोचता रहा कि शव का आखिर निपटारा कैसे किया जाए?

शव के निपटारे का कोई तरीका नहीं मिलने पर शाम को जेमिशा ने एफिड गटगटा लिया। गंभीर हालत में जेमिशा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां 19 दिनों के उपचार के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से एफिड की बोलल, 2 पैकेजिंग लॉकर पट्टी, ब्लैंड और पानी की बोतल इत्यादि बरामद किया था। पुलिस के प्राथमिक निष्कर्ष के मुताबिक जेमिशा अपनी नाबालिग प्रेमिका की हत्या की योजना के साथ ही होटल में आया था और कमरे में पहुंचने के साथ उसकी हत्या कर दी थी।

राजकोट। था। पुलिस की प्रारंभिक जांच दिन उसके शव के पास बैठा रहा और सोचता रहा कि शव का आखिर निपटारा कैसे किया जाए?

शव के निपटारे का कोई तरीका नहीं मिलने पर शाम को जेमिशा ने एफिड गटगटा लिया। गंभीर हालत में जेमिशा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां 19 दिनों के उपचार के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से एफिड की बोलल, 2 पैकेजिंग लॉकर पट्टी, ब्लैंड और पानी की बोतल इत्यादि बरामद किया था। पुलिस के प्राथमिक निष्कर्ष के मुताबिक जेमिशा अपनी नाबालिग प्रेमिका की हत्या की योजना के साथ ही होटल में आया था और कमरे में पहुंचने के साथ उसकी हत्या कर दी थी।

राज्य में 33 जिलों में 75 स्थानों पर पीएम मोदी को प्रिय बरगद के पेड़ के 'नमो वड वन' का निर्माण किया जाएगा

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देश को आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर मनाए जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय वन दिवस यानि 21 मार्च सोमवार को गुजरात में एक उदारहणीय और देश के लिए मार्गदर्शक अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को गांधीनगर में बरगद का पेड़ लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी को प्रिय बरगद के पेड़ों के 'नमो वड वन' का निर्माण करने के पर्यावरणीय अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ करवाया। 'नमो वड वन' अभियान के अंतर्गत वन विभाग द्वारा राज्य के 33 जिलों में 75 वड वन स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक वन में बरगद के 75 पेड़ लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से मनाए जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव-आजादी के 75वें वर्ष' में वन विभाग का 'नमो

वड वन' निर्माण अभियान राज्य में वटवृक्ष की पौराणिक तथा ऐतिहासिक महत्ता पुनः स्थापित करेगा इतना ही नहीं, इस अभियान से राज्य सरकार के ग्रीन कवर बढ़ाने के दृष्टिकोण को भी वेग मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 'नमो वड वन' बुलाई कार्यक्रम में 33 जिलों के 75 स्थानों पर सहभागी हुए नागरिकों तथा वन प्रेमियों को 'बाईसेम' के माध्यम से प्रेरक संदेश दिया और उनके साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि आज जब पूरा विश्व ग्लोबल वॉर्मिंग के संदर्भ से जूझ रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के मार्गदर्शन में हमने वन के साथ जन को जोड़ कर राज्य में अलग-अलग स्थानों पर वनों का निर्माण किया है। हमने वन महोत्सवों के माध्यम से अधिक से अधिक वृक्षरोपण कर ग्रीन कवर बढ़ाने का मार्ग अपनाया है। इस संदर्भ में उन्होंने जोड़ा कि कोरोना की वैश्विक महामारी ने हमें स्वच्छ प्राण वायु का महत्व समझा दिया है। ये वन महोत्सव तथा हरियाली क्रांति अधिक से अधिक पेड़ लगा कर प्राकृतिक प्राण वायु और बड़ के पेड़ जैसे अक्षय वृक्ष से स्वच्छ प्राकृतिक ऑक्सीजन प्राप्त करने में उपयुक्त बने हैं। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि बरगद के पेड़ का हमारे पुराणों में भी महत्वपूर्ण उल्लेख है। इतना ही नहीं, वटवृक्ष की उपयोगिता तथा मानव जीवन में इसके उत्करोणों को परिणामस्वरूप बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में स्थापित होने वाले बरगद के पेड़ों के 'नमो वड वन' आगामी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा तथा स्वच्छ वायु की देन सिद्ध होंगे। उन्होंने गुजरात में वन सम्पदा के संवर्द्धन, जतन तथा संरक्षण के लिए जनभागीदारी से अपनाए गए आयामों की सफलता की भूमिका दी। फ़ौरन सर्वे ऑफ़ इण्डिया की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले दो वर्षों में वृक्षच्छादित क्षेत्र में 6900 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। राज्य में वर्ष 2003 में वन क्षेत्र से बाहर लगभग 25.10 करोड़ पेड़ थे। वर्ष 2021 की वृक्ष गणना के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र से बाहर पेड़ों की संख्या 39.75 करोड़ हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथ्वी पर समग्र जीव सृष्टि के अस्तित्व के आधार समान पेड़ों, वनों तथा वनस्पतियों के जतन-संवर्द्धन की परम्परा हमारी संस्कृति में बुनी हुई है। इसीलिए पेड़ों-वन्यजीवों को आदि-अनादि काल से प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकटों वर्षों तक जीवित रहने वाले बरगद के पेड़ों की भीति सरकार के विकास कार्य भी दीर्घकालीन तथा सस्टेनेबल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी ने गुजरात में विकास कार्यों के जो बीज बोए थे, वे बीज अब विकास के वटवृक्ष बन कर करोड़ों नागरिकों को सुशासन की विशिष्ट सुख-सुविधाएँ दे रहे हैं।

एशियन ग्रैनिटो इंडिया लिमिटेड (एजीएल) ने लग्जरी सर्फेस और बाथवेयर सेगमेंट में अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए मेगा विस्तार योजना तैयार की



अहमदाबाद। देश के सबसे बड़े लकजरी सर्फेस और बाथवेयर सॉल्यूशंस ब्रांडों में से एक एशियन ग्रैनिटो इंडिया लिमिटेड (एजीआईएल) ने 500 करोड़ रुपये (70 मिलियन अमेरिकी डोलर) तक जुटाने के लिए इकटिरी शेयरों के राइड्स इश्यू के लिए ड्राफ्ट पेपर (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) दाखिल किए हैं। कंपनी ने नई निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के तहत मोरबी, गुजरात में नई अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से जीवोटी टाइल्स, सेनेटरीवेयर और एसपीसी फ्लोरांग सेगमेंट जैसे मूल्य वर्धित लकजरी सर्फेस और

बाथवेयर सेगमेंट में बड़ी विस्तार योजना तैयार की है। समूह की संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला को एक ही छत के नीचे प्रदर्शित करने के लिए कंपनी मोरबी, गुजरात में 1.5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े डिस्प्ले सेन्टर्स में से एक की स्थापना भी कर रही है। नई विनिर्माण इकाइयों के अप्रैल 2023 में वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की उम्मीद है।

एशियन ग्रैनिटो इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री कमलेश पटेल ने टिप्पणी करते हुए कहा, "भारतीय सिरेमिक टाइल उद्योग हाल के वर्षों में डबल चार्ज टाइलों से वेल्थ एडेड लार्ज फोर्मेट जीवोटी टाइलों और स्लेब में महत्वपूर्ण बदलाव देख रहा है। हालांकि, डबल चार्ज टाइलों अभी भी समग्र मांग में प्रमुख हिस्सेदारी रखती हैं और पूरे बाजार में अच्छे तरह से प्रवेश करती हैं, रलेजिंग और डिजिटल प्रिंटिंग के माध्यम से नवीन डिजाइनों के निर्माण के लिए नई तकनीकों के साथ, जीवोटी और पीजीवीटी के माध्यम से उच्च दरों पर बढ़ने की उम्मीद है। सेनेटरीवेयर में, भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा निरमाता है और विभिन्न सूक्ष्म

"द कश्मीर फाइल्स" कश्मीरी पंडितों पर अत्याचारों की वास्तविकता बताती फिल्म : हितेश आर. विश्वकर्मा



सूरत भूमि, सूरत। वास्तविकता को दर्शाने वाली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को श्री बजरंग सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हितेश आर. विश्वकर्मा द्वारा कश्मीर में रहने वाले पंडितों पर द्वारा 1990 के दशक में हुए अत्याचारों और अत्याचारों की सिनेमाहॉल में दोपहर

संगठन के कार्यकर्ताओं के फिल्म देखने के लिए सिटी प्लस सिनेमा में एक शो बुक किया गया था, और फिल्म को मुफ्त में दिखाने का आयोजन किया गया था।

1:00 बजे से 3:00 बजे को कश्मीर में रहने वाले तक का शो बुक किया पंडितों पर हुए अत्याचार गया था। श्री बजरंग को दिखाना और यह सेना के कार्यकर्ताओं, बताना था कि आखिर किस पदाधिकारियों और आम कारण कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर देश के दिखाने गई। श्री बजरंग अन्य हिस्सों में जाकर रहना सेना के पदाधिकारियों, पड़। इस फिल्म को मुफ्त कार्यकर्ताओं और आम में दिखाने का आयोजन लोगों ने बड़ी संख्या में फिल्मों देखीं।

श्री बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा फिल्म के पूरा होने के बाद उन्होंने कहा भी हिंदुओं के कल्याण के लिए ऐसी योजना बनाती का मुख्य उद्देश्य लोगों रहेगी।